

संपादकीय

बुखार का वार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से सौ से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। सिर्फ 17 दिनों के भीतर यह बीमारी एक ही जिले में तेजी से फैली। हालांकि, यह असाध्य बीमारी नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चे अस्पताल से ठीक होकर भी गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के जिला अस्पताल का दौरा कर चुके हैं।

गौरतलब है कि नेपाल की तराई में आने वाले उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और दैशाली में काफी समय से, खासकर इस मौसम में इस बीमारी का प्रभाव देखा जाता रहा है। मुजफ्फरपुर में साल 1995 में यह मामला पहली बार सामने आया था। तेज बुखार के साथ इसकी शुरुआत होती है जिसके बाद यह शरीर के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम (सायु तंत्र) पर असर करता है। इससे शरीर में छटपटाहट और मानसिक असंतुलन तक की स्थिति बन जाती है। यह बीमारी अमूमन मानसून के समय (जून से अक्टूबर के बीच) होती है। हालांकि, अप्रैल में भी इसे देखा गया है।

माना जाता है कि थोड़ी भी प्री-मॉनसून वर्षा होने पर मच्छर का प्रकोप शुरू हो जाता है जिससे यह बीमारी फैलती है। इस बार इसके शिकार ज्यादातर गरीब परिवारों के कुपोषित बच्चे हैं। इस बीमारी के बारे में यहां लोगों की जागरूकता भी कम है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के जिलों में जागरूकता अभियान चलाया गया था। हालांकि, यहां के लोग इस बात से इनकार करते हैं।

जिले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में संसाधनों की भारी कमी है। वहां के अस्पतालों में जितने मरीज पहुंच रहे हैं, उनकी तुलना में डॉक्टर और संसाधन नगण्य हैं। समस्या ने इस कारण भी इतना गंभीर रूप ले लिया। वैसे इसका टीका मौजूद है और अगर बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया गया होता तो शायद यह नौबत न आती। असल में इस तरह की बीमारियां अचानक ही धावा बोलती हैं और फिर लंबे समय तक गायब रहती हैं, इसलिए प्रशासन तंत्र निश्चित हो जाता है।

कम्मुनिटी हेल्थ को लेकर भारत में सरकारें वैसे भी बहुत सचेत नहीं रही हैं। अगर किसी इलाके में कोई खास समस्या है तो उसे ध्यानित कर वहां विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसी तरह स्वास्थ्य तंत्र का विस्तार भी सुरक्षित तरीके से हो रहा है। 2014 से ही मुजफ्फरपुर में बच्चों का एक 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की बात कही जा रही है लेकिन वह आज तक नहीं बना। क्या इस बार की त्रासदी से कोई सबक लिया जाएगा मुजफ्फरपुर हो या गोरखपुर, जहां भी इस तरह की महामारी फैलने की आशंका हो, वहां विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है। टीकाकरण के साथ-साथ झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में नियमित रूप से फॉरिंग और साफ-सफाई भी होनी चाहिए।

मैकरोनी सलाद बनाने की विधि...



विधि -

मैकरोनी सलाद रेसिपी एक बहुत ही हेल्दी व्यंजन है जिसे आप सुबह के नाश्ते के लिए तैयार कर सकती है। यह मूल रूप से बहुत ही कम बसा वाली रेसिपी है जिसे आप अपने बच्चे के लंबे बॉक्स में पैक कर सकती है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट है और साथ ही

कई पोषक तत्वों और खनियों का भरपूर मिश्रण भी है। आइए जानते हैं मैकरोनी सलाद बनाने की विधि के बारे में।

सामग्री -

पास्ता मैकरोनी (उबले हुए) - 2 कप

बीन (उबले हुए) - 1/2 कप

गाजर (उबले हुए) - 1/2 कप

खीरा (कटे हुए) - 1

बादाम (टोस्टेड) - 1/4 कप

धनिया पत्ते (कटे हुए) - 1

चमच

लो फैट दही - 200 ग्राम

एअर इंडिया को बेचने की हो रही एक और कोशिश

मुंबई। देश की सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया की बिक्री को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव में कच्चे तेल की कीमतों एवं विनियम दर में उत्तर-चढ़ाव, बृहत माहौल में बदलाव एवं अन्य कारणों को गिनाया गया था। फिलहाल, वित्त मंत्रालय के नए प्रस्ताव को एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (AISAM) के पास भेजा जाएगा। AISAM वो समझ है जिसमें वित्त और विनियम दर में उत्तर-चढ़ाव जैसे मुद्दों को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी ईवाई ने एक रिपोर्ट प्राप्त किया गया था। इन कारणों में सरकार की 24 फीसदी हिस्सेदारी, अत्यधिक कर्ज, मुताबिक एक अधिकारी ने

वजह से एअर इंडिया को कोई खरीदार नहीं मिला था। दरअसल, सरकार ने पिछले साल एअर इंडिया की 76 फीसदी हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण के लिए बोलियां आपूर्ति की थीं लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। इसके बाद विलय और अधिग्रहण को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी ईवाई ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बिक्री प्रक्रिया के विफल रहने के कारणों का उल्लेख किया गया था। इन कारणों में सरकार की 24 फीसदी हिस्सेदारी, अत्यधिक कर्ज, मुताबिक एक अधिकारी ने

कच्चे तेल की कीमतों एवं विनियम दर में उत्तर-चढ़ाव, बृहत माहौल में बदलाव एवं अन्य कारणों को गिनाया गया था। फिलहाल, वित्त मंत्रालय के नए प्रस्ताव को एअर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (AISAM) के पास भेजा जाएगा। AISAM वो समझ है जिसमें वित्त और विनियम दर में उत्तर-चढ़ाव जैसे मुद्दों को भी शमिल होते हैं।

बताया कि ईवाई की रिपोर्ट पर पिछले साल जून में AISAM की बैठक में चर्चा हुई थी। इसके बाद एअर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया को टाल दिया गया था। अधिकारी ने कहा, 'हम एअर इंडिया की बिक्री को यह तय करना होगा कि सरकार 100 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री करेगी या 76 फीसदी की।'

के समक्ष रखेंगे। पिछले साल एअर इंडिया के विनियोग के विफल रहने के बाद उत्तर एवं मुद्दों को भी शमिल होते हैं।

ईवाई की रिपोर्ट पर

AISAM ने की थी चर्चा

न्यूज एजेंसी पीटीआई के

विनियम दर में उत्तर-चढ़ाव से जुड़े

विन